reign investment for 1989-90 through 1992-93 are given in Table 2.

Table 2

Foreign Exchange Receipts (Gross)
US $ million

(US$ million)

	1989-90	1990-91	1991-92 (Estimate)	1992-93
Current receipts including grants but excluding Private transfers.	22229	23859	23721	24680
Capital receipts.				
(i) external assistance	3002	3397	4318	3381
(ii) commercial borrowing . . .	2897	4562	3025@@	1188
(iii) IMF	..	1858	1240	1623

@@ Including India Development Bonds.

(c) The plan outlays for industrial sector including village and small industries for the State of Tamil Nadu during 1990-91 to 1993-94 has been as follows:

Year	Plan outlay (Rs. crore)
1990-91 . . .	93.80
1991-92. . . .	123.10
1992-93. . .	104.60
1993-94. . . .	115.45

(d) There is no specific allotment for industrial development of backward areas. However, under the Growth Centre Scheme for development of infrastructural facilities, Rs. 3.5 crores have been released towards central assistance to the Government of Tamil Nadu.

वित्तीय संस्थाओं को राज-सहायता

2111. श्री राम जेठमलानी :
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक प्रत्यय और विनिधान निगम और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं को वित्तीय राज-सहायता दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् वर्ष 1990–91, 1991–92 और 1992–93 में राज-सहायता के रूप में उन्हें कितनी-कितनी राशि दी गई है ,

(ग) क्या यह भी सच है कि इन संस्थाओं द्वारा मुख्यत: ब्याज पर ऋण [illegible] किया जाता है ;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं ;

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन संस्थाओं की कुल पूंजी का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(च) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान इन संस्थाओं को, अलग-अलग वर्षों में, कोई ऋण दिये जाते रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो इन राशियों का ब्यौरा क्या है तथा इन संस्थाओं को वित्त-सहायता देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अब्दार अहमद) :(क) और (ख) सरकार द्वारा अथवा भारतीय रिजर्व बैंक से अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय दिये जाने की कोई योजना नहीं है । अलबत्ता भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के मामले में 31 मार्च, 1991 का समाप्त हुए वर्ष तक आय की तुलना में व्यय का आधिक्य भारत सरकार से प्राप्य राशियों से पूरा किया जाना था। वर्ष 1990–91, 1991–92 और 1992–93 के दौरान आई.आर.बी.आई. को इस प्रयोजन के लिए क्रमशः 2 करोड़ रु०, 5 करोड़ रु० और 5 करोड़ रु० की राशि की प्रतिपूर्ति की गई।

(ग) और (घ) वित्तीय संस्थाएं उद्योग को समय-समय पर निर्धारित ब्याज दरों के अनुसार ऋण मंजूर करती हैं।

(ङ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में आई.डी.बी.आई., आई.एफ.सी.आई., आई.सी.आई.सी.आई. और आई.आर.बी.आई. के संबंध में चुकता शेयर पूंजी का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

रकम (करोड़ रु० में)

	1990–91	1991–92	1992–93
आई.डी.बी.आई.	703.0	753.0	753.0
आई.एफ.सी.आई.	135.0	142.5	202.5
आई.सी.आई.सी.आई.	114.6	170.7	241.1
आई.आर.बी.आई.	155.3	175.3	175.3

(च) और (छ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में सरकार द्वारा आई.डी.बी.आई. आई.एफ.सी.आई, आई.सी.आई.सी.आई. और आई.आर.बी.आई. को प्रतिरूप निधियों समेत दिये गये ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(करोड़ रु० में)

	1990–91	1991–92	1992–93
आई.डी.बी.आई.	108.8	110.7	175.0
आई.एफ.सी.आई.	1.8	2.2	2.8
आई.सी.आई.सी.आई.	77.3	107.3	183.9
आई.आर.बी.आई.	14.0	24.0	10.0